

[2023] 10 एस. सी. आर 464:2023 आई. एन. एस. सी 623 ए

ए.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v.

श्याम बिहारी और अन्य (2013 की आपराधिक अपील संख्या 413) 17 जुलाई, 2023
बी.

[बी. वी. नागरत्ना और मनोज मिश्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302 और 34-हत्या का मामला-पीड़ित के साथ यात्रा कर रहे अभियोजन पक्ष के गवाहों ने, हालांकि एक अलग स्कूटर पर, रात में स्कूटर की रोशनी में पीड़ित के साथ यात्रा करते हुए तीन पुलिसकर्मियों को हथियारों से लैस सड़क पर देखा-पुलिसकर्मियों ने उन पर गोलीबारी की, पीड़ित को मारा, जिसने दम तोड़ दिया और अभियोजन पक्ष के गवाह भागने में कामयाब रहे-गश्त करते हुए हत्या का आरोप लगाए गए पुलिसकर्मी।302/34 - हालांकि, निचली विचारण न्यायालय द्वारा बरी किया जाना-इसके खिलाफ यू/एस के तहत अपील।378(3) - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:हालांकि उच्च न्यायालय का निर्णय एक गुप्त है, लेकिन यह अपने आप में आदेश को अपास्त करनाने के लिए एक आधार होने की आवश्यकता नहीं है-अभियोजन पक्ष के मामले की योग्यता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड हैं-घटना वर्ष 1987 में उत्पन्न हुई और अपील लंबित रही-अभियोजन पक्ष के गवाहों में से कोई भी तीन अभियुक्तों में से किसी की पहचान नहीं कर सका-उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि अपराध में शामिल तीन पुलिसकर्मी वे थे जो मुकदमे का सामना कर रहे थे-निचली न्यायालय ने चश्मदीद गवाह की गवाही को खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया-इसके अलावा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि आग का आदान-प्रदान हत्या के उद्देश्य से था-इसके अलावा, पीड़ित की मौत हत्या से हुई।12 बोर गन शॉट जिसे पुलिसकर्मियों को जारी की गई राइफलों से जोड़ा नहीं जा सकता था-परिस्थितियों को अब तक एक पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए थी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं में मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति थे और किसी और ने अपराध नहीं किया था-हालाँकि, जो परिस्थितियाँ साबित हुईं वे एक पूर्ण श्रृंखला का गठन नहीं करती हैं-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 378 (3)।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 378 (3)-दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपील-अपीलीय न्यायालय की शक्ति-समझाया गया।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश थोड़ा गुप्त प्रतीत होता है, लेकिन यह अपने आप में एक आधार होने की आवश्यकता नहीं है

एच.

464

465

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य ए

आदेश को अपास्त करना और मामले को उच्च न्यायालय को भेजना, विशेष रूप से जब अभियोजन मामले की योग्यता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड हो। इसके अलावा, क्योंकि यह घटना वर्ष **1987** की है और अपील एक दशक से अधिक समय से लंबित है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि मामला केवल निर्णय को फिर से लिखने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा जाता है, तो यह न्याय का उपहास होगा। नतीजतन, चूंकि निचली विचारण न्यायालय ने मामले पर बहुत विस्तार से विचार किया है और सबूत के प्रत्येक टुकड़े पर चर्चा की है, जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है, इसलिए यह आकलन करना उचित होगा कि क्या निचली विचारण न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं देकर न्याय की विफलता हुई है। [पैरा **26**] [474-एच; 475-ए-सी]

बी.

सी.

1.2 बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, अपीलीय न्यायालय की साक्ष्य की पुनः सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति किसी भी सीमा से सीमित नहीं है। लेकिन यह समान रूप से तय किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को बरी करने के आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि एक विपरीत दृष्टिकोण स्वीकार्य है, विशेष रूप से, जहां निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और अभिलेख पर प्रासंगिक साक्ष्य की अज्ञानता/गलत अध्ययन से दूषित नहीं है। [पैरा **27**] [475-सी. डी.] **1.3** तत्काल मामले

में अभियोजन पक्ष का मामला नेत्र संबंधी कारणों के साथ-साथ कुछ परिस्थितियों पर भी आधारित था। नेत्र खाता पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-15 द्वारा प्रदान किया जाता है। पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 मृतक के साथ यात्रा कर रहे थे, हालांकि एक अलग स्कूटर पर। इसलिए, उन्हें इस घटना को देखने का अवसर मिला। उनके अनुसार, जब वे अपने-अपने स्कूटरों पर यात्रा कर रहे थे, तो पुलिस की वर्दी में पुरुषों ने उन पर मशाल की रोशनी चलाई। नतीजतन, मृतक का स्कूटर फिसल गया। इसके बाद, जब गोलियां चलाई गईं तो वे भाग गए और गाँव आ गए। सूचना पर गाँव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। न तो पीडब्लू-3 और न ही पीडब्लू-6 तीनों अभियुक्तों में से किसी की पहचान कर सके। उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि अपराध में शामिल तीन पुलिसकर्मी वे थे जो मुकदमे का सामना कर रहे थे। इस प्रकार, निचली विचारण न्यायालय के विचार में कोई दुर्बलता, बहुत कम विकृति नहीं है कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की गवाही मुकदमे का सामना कर रहे तीन अभियुक्तों के लिए अभियोजन पक्ष के लिए बहुत मददगार नहीं है। [पैरा 28] [475-ई-जी]

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.4 पीडब्लू-15 की गवाही के संबंध में, निचली विचारण न्यायालय द्वारा उसे अविश्वसनीय ठहराने के लिए विस्तृत कारण दर्ज किए गए हैं और

एच.

466 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

श्रेय के योग्य नहीं। इसके अलावा, पीडब्लू-15 की उपस्थिति की पुष्टि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 द्वारा नहीं की गई है। अन्यथा भी, पीडब्लू-15 का एक सप्ताह से अधिक समय तक चुप रहने का आचरण मन में एक स्थायी संदेह पैदा करता है कि क्या वह सलाह पर स्थापित एक गवाह है, विशेष रूप से जब यह देखा जाता है कि उसका पहला बयान जांच एजेंसी को नहीं था, बल्कि एक वकील द्वारा तैयार किए गए एक हलफनामे पर दिया गया था, जिसने एक साथ तीन हलफनामे तैयार किए थे। निचली विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया और यह भी कि पीडब्लू-15 झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वह हलफनामा तैयार करने के लिए अकेले गया था। निचली विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि तीनों हलफनामे स्टाम्प पेपरों पर तैयार किए गए थे, लगातार क्रमांकित, एक ही विक्रेता से खरीदे गए थे और हलफनामों को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचाते हुए त्वरित उत्तराधिकार में शपथ ली गई थी कि वे एक वकील द्वारा तैयार किए गए थे। निचली विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि पीडब्लू-15 का आचरण इस मायने में थोड़ा असामान्य था कि उसने मृतक के पिता सहित

किसी को भी कोई खुलासा नहीं किया, वह तुरंत शपथ लेने गया और पुलिस के एक उच्च अधिकारी को डाक द्वारा एक हलफनामा भेजा, भले ही उस समय तक, जांच स्थानीय पुलिस से सीबी-सी. आई. डी. को स्थानांतरित कर दी गई थी और इसलिए, स्थानीय पुलिस से कोई खतरा नहीं था। इन परिस्थितियों में, यदि निचली विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-15 की गवाही को खारिज कर दिया, तो यह उचित था। [पैरा 29] [475-एच; 476-ए-डी]

बी.

सी.

डी.

ई.

1.5 सिद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो बात सामने आती है वह यह है कि गवाहों का कहना है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को पुलिस कार्रवाई हुई थी। यह मानते हुए कि यह सच है कि रात में वर्दी में पुरुषों और जनता के सदस्यों के बीच गोलीबारी हुई थी, लेकिन इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि गोलीबारी हत्या के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, मृतक की मौत राइफल की गोली से नहीं हुई थी। बल्कि, वह ए से मर गया। **12** गोली का निशान था जिसे आरोपी व्यक्तियों को जारी की गई राइफलों से जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए, भले ही आरोपी को जारी की गई सर्विस राइफलों से संबंधित राइफल के कारतुसों के खाली हिस्से मौके पर पाए गए हों, लेकिन मृतक की मौत के लिए आरोपी व्यक्तियों का दोष अनुमानित नहीं है। इसके अलावा, ए की कोई वसूली नहीं है। **12** मुकदमे का सामना कर रहे किसी भी आरोपी व्यक्ति से बंदूक ले। विशेष रूप से, घटना के बाद, ग्रामीण अपराध स्थल पर जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, इस अवधि के दौरान आरोपी व्यक्ति मौके पर मौजूद थे। इसलिए, अगर वे वास्तव में ए थे

एफ.

जी.

एच.

467

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य ए

पी. डब्ल्यू. **3** या पी. डब्ल्यू. **6** द्वारा उनकी पहचान की जा सकती थी, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं थी। इसके अलावा, घटनास्थल पर अभियुक्त की निरंतर उपस्थिति एक ऐसी परिस्थिति है जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है, एक ऐसा आचरण जो एक दोषी दिमाग को

नकारता है। एक अन्य परिस्थिति जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है, वह यह है कि अभियोजन पक्ष के अपने मामले के अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या तीन थी, प्रत्येक के पास **50** गोलियों वाली एक राइफल थी। माना जा सकता है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर पाए गए कुछ खाली कारतूस आरोपी को जारी की गई राइफल से नहीं दागे गए थे। यह किसी अन्य राइफल की उपस्थिति का भी संकेत है। यह किसकी राइफल थी, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य मौन हैं। इसके अलावा, अगर आरोपी गोली चलाने के लिए अपनी राइफल का उपयोग करते तो वे मृतक को चोट पहुँचाने के लिए देसी पिस्तौल का उपयोग क्यों करते। [पैरा **30** और **31**] **[476-ई-एच; 477-ए-बी]**

बी.

सी.

1.6 यह परिस्थिति कि अभियुक्त व्यक्तियों को उस क्षेत्र में गश्त करने की आवश्यकता थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उस उद्देश्य के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था, एक ऐसी परिस्थिति है जो निर्णायक नहीं है कि अभियुक्तों पर आरोप लगाया जाए, क्योंकि गश्त क्षेत्र दो गाँवों में फैला हुआ था। यह संभव है कि आरोपी देर से मौके पर पहुँचे, जब घटना पहले ही हो चुकी थी, और उपद्रवियों को भगाने के लिए, उनकी सर्विस राइफलों से गोलियां चलाईं। जो भी हो, एक बार जब परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए पीडब्लू-**15** के ऑक्युलर खाते को खारिज कर दिया गया, तो परिस्थितियों को अब तक एक पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए थी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं में मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति थे और कोई और नहीं जिसने अपराध किया था। यहां जो परिस्थितियां साबित हुई हैं, वे अब तक एक पूरी श्रृंखला का गठन नहीं करती हैं जो यह इंगित करती हैं कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह आरोपी व्यक्ति थे और कोई और नहीं जिसने अपराध किया था। ऐसी स्थिति में निचली विचारण न्यायालय के पास आरोपी को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह इंगित नहीं किया गया है कि निचली विचारण न्यायालय ने किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य को नजरअंदाज या गलत पढ़ा है। [पैरा **32,33**] **[477-सी-ई]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.7 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना और मामले को केवल उच्च न्यायालय को निर्णय को फिर से लिखने के लिए भेजना एक उपयुक्त मामला नहीं है, क्योंकि यह व्यर्थ की कवायद होगी। [पैरा **34**] **[477-एफ]**

एच.

468

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2013 की आपराधिक अपील No.413।

2012 के जी. ए. सं. 4 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 26.07.2012 के निर्णय और आदेश से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौरसिया, शुभेंदु आनंद, तथागट शर्मा, त्रिंग चामविबो जेलियांग, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।
बी.

अनिल के. शर्मा, संजीव कुमार, प्रवीण चतुर्वेदी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

मनोज मिश्रा, जे.

1. यह अपील नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय"), दिनांक 26.07.2012, 2022 की सरकारी अपील संख्या 4 में आरोप लगाती है। उक्त आदेश द्वारा, हालांकि तीसरे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सी. बी. आई., देहरादून (संक्षेप में "निचली अदालत") द्वारा सी. नं. 1 में पारित बरी किए जाने के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील करने में देरी। आर. सी.-5/87-SIU.II को माफ कर दिया गया, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 378 (3) के तहत अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप सरकारी अपील को खारिज कर दिया गया।

डी.

ई.

परिचयात्मक तथ्य

2. 24.06.1987 की रात/देर शाम को, एक राज कुमार बलियान (संक्षेप में, "मृतक") की हत्या कर दी गई थी। प्रमोद कुमार त्यागी (पीडब्लू-6) द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह और एक स्कूटर पर सुदीप

(पीडब्लू-3) और दूसरे स्कूटर पर राज कुमार बालियान (मृतक) मुजफ्फरनगर से मीरापुर जा रहे थे, तो लगभग 9:30 बजे, स्कूटर की रोशनी में, उन्होंने तीन पुलिसकर्मियों को सड़क पर खड़े देखा। उनमें से एक के पास डंडा (छड़ी) थी जबकि अन्य दो के पास राइफलें थीं। जिस व्यक्ति के पास डंडा था, उसने उन पर मशाल की रोशनी चलाई। नतीजतन, उन्होंने अपने-अपने स्कूटरों पर नियंत्रण खो दिया, जो फिसल गए और गिर गए। एक पुलिसकर्मी ने मारने के लिए गोली चलाने का आह्वान किया। नतीजतन, मृतक को गोली मार दी गई, जो मौके पर ही गिर गया। हालाँकि, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 गाँव भागने में कामयाब रहे। सूचना पर ग्रामीण अपराध स्थल पर पहुंचे और ए ने भी ऐसा ही किया

एफ.

जी.

एच.

469

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य [मनोज मिश्रा, जे.] ए.

पुलिस। पुलिस की मौजूदगी में मृतक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद, शव को अस्पताल ले जाया गया और शव को वहां छोड़ने के बाद, पीडब्लू-6 ने प्राथमिकी दर्ज की, जिसे पी. एस. सिखेरा में केस क्राइम No.48/87 के रूप में दर्ज किया गया। 3. घटना का एक अन्य संस्करण महिंद्रा सिंह के कहने पर 25.06.1987 पर दर्ज किया गया था, जिसने केस क्राइम No.48A/87 को जन्म दिया। वहाँ यह आरोप लगाया गया था कि 26.05.1987 पर गाँव में एक डकैती हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। चूंकि अपराधी तब से नियमित रूप से गाँव का दौरा कर रहे थे, इसलिए गाँव वालों के साथ-साथ क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस द्वारा भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि जब तीन पुलिस कांस्टेबल गाँव में गश्त कर रहे थे और गाँव के लोग रात को लगभग 9 बजे नज़र रख रहे थे, तो एक आदमी आया और शोर मचाया कि पाँच-छह अपराधी मोटरसाइकिल और स्कूटर पर गाँव आने वाले थे। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। लगभग 9:30 बजे, एक मोटरसाइकिल आई और भटोदा मोड़ से थोड़ा पहले रुकी। इसके बाद दो स्कूटर तेज गति से आए। जब मशाल की रोशनी दिखाई दी और स्कूटरों को रुकने का संकेत दिया गया, तो सवार ने ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को मारने के लिए गोली चला दी। लेकिन, एक स्कूटर फिसल गया और दूसरा रुक गया। हालाँकि अपराधी गोली चलाते हुए भागने लगे। नतीजतन, पुलिस और ग्रामीणों द्वारा जवाबी गोलीबारी की गई। एक अपराधी का ग्रामीणों ने पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उनके द्वारा उसकी पिटाई भी की गई। उस समय पी. एस. सिखेरा से एक इंस्पेक्टर एम्बेसेडर कार में आया। उसने अपराधी से पूछताछ की। बाद में, कई ग्रामीण पहुंचे और बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति राज कुमार, अधिवक्ता है। इसके बाद राजकुमार

को अस्पताल ले जाया गया।उसी समय, घटनास्थल की तलाशी ली गई और घटनास्थल से गोलियों के दो खाली गोले बरामद किए गए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

4. उपरोक्त दो मामलों की जांच सी. बी.-सी. आई. डी. को सौंपी गई थी और बाद में, आगे की जांच के लिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) को सौंपी गई थी, जिस पर सी. बी. आई. ने एक मामला सहपठित किया। पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देहरादून की न्यायालय ने अनिल कुमार, श्याम बिहारी और अरशद अली (प्रतिवादी) पर निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया।

जी.

एच.

470

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

धारा 32 आई. पी. सी. सहपठित धारा 302 अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 33 गवाहों की जांच की और जी. डी. प्रविष्टियों, जब्ती ज्ञापन, स्थल योजना, फोरेंसिक रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट आदि के संबंध में विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। जाँच के दौरान जब्त की गई वस्तुओं जैसे विभिन्न सामग्री प्रदर्शनों को परीक्षण के दौरान प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया था।

बी.

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों को संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए अभियुक्तों के सामने रखा गया था।अपने बयान में, संहिता की धारा 313 के तहत,

अभियुक्तों ने उनके खिलाफ पेश होने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और बलि का बकरा बनाया गया है।

सी.

अभियोजन साक्ष्य की प्रकृति

7. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित प्रभाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप को घर लाने की मांग की:- (i) घटना की तारीख, समय और स्थान पर, तीनों आरोपी पिकेट ड्यूटी पर थे जैसा कि संबंधित पुलिस स्टेशन में की गई जी. डी. प्रविष्टियों से पता चलता है;

डी.

((ii) जी. डी. प्रविष्टियों से पता चलता है कि वे एक राइफल और 50-50 गोलियों के साथ पुलिस स्टेशन से रवाना हुए थे।

ई.

(iii) बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि घटनास्थल से बरामद कुछ खाली राइफल कारतूस अभियुक्तों की सर्विस राइफलों से दागे गए थे, जिससे मौके पर उनकी उपस्थिति की पुष्टि हुई।

एफ.

(iv) पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 ने बताया कि गोली पुलिस वालों द्वारा चलाई गई थी जिन्होंने स्कूटर सवारों पर मशाल की रोशनी दिखाई; (v) पीडब्लू-15 (श्याम सिंह) ने अपराध में तीन अभियुक्तों की भागीदारी की पुष्टि की और साबित किया कि अन्य दो अभियुक्तों के प्रोत्साहन पर, अनिल कुमार ने एक देसी पिस्तौल निकाली और मृतक पर गोली चलाई थी।

जी.

(vi) घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा था कि तीन आरोपी अन्य लोगों के साथ मौके पर मौजूद थे।

एच.

471

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य [मनोज मिश्रा, जे.] ए.

(vii) पुलिस ने घटना का एक झूठा क्रॉस संस्करण स्थापित किया, जिसका नाम केस क्राइम नंबर 48 ए/87 है, जो इंगित करता है कि पुलिस की ओर से कानून के चंगुल से खुद को बचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

बी.

8. निचली विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की गवाही को महत्वहीन पाया क्योंकि दोनों गवाहों ने यह नहीं कहा कि अपराध में शामिल पुलिसकर्मी मुकदमे का सामना कर रहे थे। बल्कि, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्त को पहले नहीं देखा था और अभियुक्तों को पहचान के लिए नहीं रखा गया था।

सी.

9. प्रत्यक्षदर्शी श्याम सिंह (पीडब्लू15) के संबंध में, निचली विचारण न्यायालय ने उन्हें निम्नलिखित कारणों से अविश्वसनीय पाया। (क) पीडब्लू15 ने घटना के बारे में अपनी जानकारी का कोई त्वरित खुलासा नहीं किया और दोषियों ने पुलिस या ग्रामीणों को, बल्कि कई दिनों के अंतराल के बाद, एक शपथ पत्र देने और पुलिस के एक उच्च अधिकारी को डाक द्वारा भेजने का फैसला किया; (ख) पीडब्लू15 सहित तीन शपथ पत्र, एक ही भाषा में एक ही प्रकटीकरण करते हुए, एक ही दिन में, कमोबेश एक ही समय में, और एक ही वकील द्वारा तैयार किए गए, कुछ दिनों के बाद पुलिस को प्राप्त हुए; और (ग) पीडब्लू15 ने झूठ बोला कि जब वह शपथ पत्र लेने गया तो वह अकेला था।

डी.

10. पीडब्लू-15 के चश्मदीद गवाह के खाते को खारिज करने और पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 के चश्मदीद गवाह के खातों को आरोपी को शामिल करने के लिए अप्रासंगिक पाते हुए, निचली विचारण न्यायालय ने अन्य परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े, जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया था। ये थे: (क) आरोपी को जारी की गई राइफलों से मौके से उठाए गए कुछ खाली कार्ट्रिज के गोले दागे गए पाए गए; और (ख) 1987 के केस क्राइम No.48A के माध्यम से घटना का गलत विवरण स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

11. अभियुक्त की सर्विस राइफलों से मेल खाने वाले कुछ खाली कारतुसों के संबंध में, निचली विचारण न्यायालय ने देखा कि चार में से 303 अपराध स्थल से बरामद किए गए कारतुसों में से एक आरोपी अनिल की राइफल से, एक आरोपी श्याम बिहारी की राइफल से दागा गया था, जबकि शेष दो कारतुस तीन आरोपी व्यक्तियों में से किसी की भी सर्विस राइफल से नहीं दागे गए थे। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं था कि किसकी राइफल से शेष दो गोलियां चलाई गईं। निचली विचारण न्यायालय के अनुसार, इस विसंगति ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के बयान को संदिग्ध बना दिया क्योंकि इसमें किसी अन्य व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

472

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

12. उपरोक्त के अलावा, निचली विचारण न्यायालय ने शव परीक्षण रिपोर्ट से देखा कि मृतक को लगी बंदूक की गोली की चोट राइफल की गोली से नहीं बल्कि एक गोली से लगी थी।¹² हथियार था जो किसी भी आरोपी व्यक्ति से बरामद नहीं किया गया था। इसलिए, भले ही मौके पर राइफल की गोलियां मिली हों, लेकिन वे वे नहीं थीं जिनसे मृतक को चोटें आई थीं। घटना के क्रॉस संस्करण (यानी केस क्राइम No.48A/87) के संबंध में, अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया था क्योंकि यह उनके कहने पर नहीं था।

बी.

13. उपरोक्त के अलावा, निचली विचारण न्यायालय ने देखा कि अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, कई व्यक्ति (यानी पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 और पुलिस कर्मियों सहित ग्रामीण) मौके पर पहुंचे थे और तीन आरोपी भी वहां मौजूद थे, फिर भी उनकी पहचान नहीं की गई। इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6, जो मृतक के निकट किसी अन्य स्कूटर पर यात्रा कर रहे थे, ने आरोपी व्यक्तियों को पहचान लिया होता, तो वे अपराध स्थल पर उनकी पहचान उन लोगों के रूप में करते जिन्होंने मृतक की हत्या की थी, और देश में बनी पिस्तौल भी बरामद की जा सकती थी।

सी.

डी.

14. अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद, निचली विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि वर्दी में वे तीन पुलिसकर्मी, जिन्होंने राज कुमार बलियान (मृतक) पर हमला किया था, वे लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे।

ई.

उच्च न्यायालय की टिप्पणियां

15. मुकदमे में सफल होने में विफल रहने के बाद, राज्य ने विलंब माफी आवेदन और अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन के साथ एक समयबद्ध अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा विलंब माफी आवेदन को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया।

16. अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने देखा कि अभियोजन पक्ष का मामला तीन चश्मदीद गवाहों के खातों पर आधारित है। प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 पुलिसकर्मियों की पहचान नहीं कर सके और जहां तक पीडब्लू-15 का संबंध है, वह विश्वसनीय नहीं पाया गया। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य ने संकेत दिया कि मृतक की मृत्यु एक गोली से गोली लगने से हुई थी। 12 अभियुक्त के पास राइफल नहीं थी, बल्कि धार हथियार था, इसलिए औपचारिक रूप से अपील की सुनवाई करने के लिए अनुमति देना व्यर्थ में एक अभ्यास होगा।

एफ.

जी.

17. हमने श्री राजन कुमार चौरसिया की सहायता से अपर सॉलिसिटर जनरल श्री विक्रमजीत बनर्जी को विद्वान है।

एच.

473

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य [मनोज मिश्रा, जे.] ए.

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता; श्री अनिल के. शर्मा, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता; और अभिलेख का अवलोकन विद्वान है।

प्रस्तुतियाँ

18. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें यह संदेह से परे साबित हो गया था कि मृतक को उन व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई थी जो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। घटना की रात, तीन आरोपी, श्याम बिहारी, अनिल कुमार शर्मा और अरशद अली, सभी सशस्त्र कांस्टेबल, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के अनुसार, क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद ये सिपाही मौके पर मौजूद पाए गए। इसलिए, अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति की पुष्टि न केवल चश्मदीद गवाहों द्वारा की गई थी, बल्कि इस तथ्य सहित परिस्थितियों से भी की गई थी कि घटनास्थल से बरामद कुछ खाली कारतूस उनकी सर्विस राइफलों से दागे गए थे। इस प्रकार, न केवल उनकी उपस्थिति साबित हुई, बल्कि घटना के एक अन्य संस्करण यानी 1987 के केस क्राइम No.48A ने पुलिस कार्रवाई को दर्शाते हुए पुष्टि की कि मृत्यु पुलिस कार्रवाई का परिणाम थी। इसलिए, अभियुक्त पर इन दोषपूर्ण परिस्थितियों को

समझाने का बोझ भारी था और इसके अभाव में, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।**19.** यह भी तर्क दिया गया कि भले ही पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सके, उन्होंने घटना के तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि की और इसलिए, उनकी गवाही का उपयोग पीडब्लू-15 की गवाही की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, जिन्होंने न केवल घटना का वर्णन किया, बल्कि आरोपी व्यक्तियों को पहचान और पहचान कर सकते थे।

बी.

सी.

डी.

ई.

20. इस प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, निचली अदालत का फैसला विकृत था और अपील करने की अनुमति मांगने वाले आवेदन की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुई है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि अपील की अनुमति दी जाए और गुण-दोष पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजा जाए।

एफ.

21. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, सबसे पहले, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5, जो मृतक के साथ यात्रा कर रहे थे, अभियुक्तों की पहचान उन लोगों के रूप में नहीं कर पाए हैं जो मृतक की हत्या में शामिल थे; और, दूसरा, मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली के घाव से हुई थी, जिसे एक गंभीर चोट के रूप में माना जा सकता है।**12** उसके पास हथियार था, न कि एक राइफल जो आरोपी के पास थी। इसके अलावा, मौके से उठाए गए कुछ खाली कारतूस तीन अभियुक्तों की राइफलों से मेल नहीं खाते थे, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि कोई और भी मौजूद था

जी.

एच.

474

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

एक राइफल के साथ और इसका इस्तेमाल किया था। इन परिस्थितियों में, यदि निचली विचारण न्यायालय आरोपी को संदेह का लाभ देती है, तो निचली विचारण न्यायालय के फैसले

और आदेश को किसी अपील में उलट आदेश के रूप में विकृत नहीं माना जा सकता है।²². पीडब्लू-15 की गवाही के संबंध में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-15 को कई कारणों से विश्वसनीय नहीं पाया गया है। सबसे पहले, उन्होंने किसी को भी इस घटना के गवाह होने का खुलासा नहीं किया, भले ही ग्रामीण मौके पर आ गए थे और पर्याप्त संख्या में इकट्ठा हो गए थे ताकि किसी भी व्यक्ति में विश्वास पैदा किया जा सके कि वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ खुलासा कर सकता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो। दूसरा, जांच एजेंसी को अपना बयान देने के बजाय, गवाह ने एक वकील से एक हलफनामा तैयार कराया, जिसने एक नहीं बल्कि तीन हलफनामे तैयार किए, जो समान रूप से लिखे गए थे। एक पीडब्लू-15 का था और अन्य दो उन दो व्यक्तियों में से थे जो मुकदमे के दौरान गवाह के रूप में पेश नहीं हो सके थे। यह इंगित करता है कि वे शपथ पत्र कानूनी सलाह पर तैयार किए गए थे। तीसरा, पीडब्लू-15 का यह कथन कि अनिल कुमार ने मृतक को गोली मारने के लिए देसी पिस्तौल निकाली थी, दो कारणों से असंभव प्रतीत होता है, अर्थात्, इस तरह का कार्य करने का कोई सिद्ध उद्देश्य नहीं था और एक बार जब वे पहले ही अपनी राइफलों से गोली चला चुके होते तो वे आसानी से घटना को मुठभेड़ का रंग देकर मृतक को मारने के लिए इसका उपयोग कर सकते थे।²³. घटनास्थल पर अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति, गोली चलाने के लिए सर्विस राइफल का उपयोग और पुलिसकर्मियों द्वारा मृतक की हत्या जैसी आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि वे अपने आप में एक पूरी श्रृंखला बनाने के लिए अपर्याप्त हैं जो यह इंगित करता है कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह आरोपी थे और कोई और नहीं जिसने अपराध किया था। बल्कि, ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद थीं, जो अभिलेख पर सिद्ध हुई थीं, जैसे कि मौके पर कुछ खाली गोलियों की उपस्थिति जो तीन अभियुक्तों को जारी की गई राइफलों से नहीं दागे गए थे, जो किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का भी संकेत देती थी और घटना की संभावना अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने के अलावा किसी अन्य तरीके से होने की थी।²⁴. उपरोक्त सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश में हस्तक्षेप किया जाए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

विश्लेषण

25. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

26. शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश थोड़ा गुप्त प्रतीत होता है, लेकिन इसके लिए अपने आप में ए की आवश्यकता है।

एच.

475

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य [मनोज मिश्रा, जे.] ए.

यह हमारे लिए आदेश को अपास्त करवाने और मामले को उच्च न्यायालय को भेजने का आधार नहीं है, विशेष रूप से जब हमारे पास अभियोजन मामले की योग्यता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा, क्योंकि यह घटना वर्ष 1987 की है और अपील एक दशक से अधिक समय से लंबित है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि हम मामले को केवल निर्णय को फिर से लिखने के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हैं, तो यह न्याय का उपहास होगा। नतीजतन, चूंकि निचली विचारण न्यायालय ने मामले पर बहुत विस्तार से विचार किया है और सबूत के प्रत्येक टुकड़े पर चर्चा की है, जिस पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है, इसलिए हमारे लिए यह आकलन करना उचित होगा कि क्या निचली विचारण न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं देकर न्याय की विफलता हुई है।

बी.

सी.

27. यह एक साधारण कानून है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, अपीलीय न्यायालय की साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति किसी भी सीमा से सीमित नहीं है। लेकिन यह समान रूप से तय किया गया है कि अपीलीय न्यायालय को बरी करने के आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि एक विपरीत दृष्टिकोण स्वीकार्य है, विशेष रूप से, जहां निचली विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और अभिलेख पर प्रासंगिक साक्ष्य की अज्ञानता/गलत अध्ययन से दूषित नहीं है।

डी.

28. तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला नेत्र संबंधी कारणों के साथ-साथ कुछ परिस्थितियों पर भी आधारित था। नेत्र खाता पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-15 द्वारा प्रदान किया जाता है। पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 मृतक के साथ यात्रा कर रहे थे, हालांकि एक अलग स्कूटर पर। इसलिए, उन्हें इस घटना को देखने का अवसर मिला। उनके अनुसार, जब वे अपने-अपने स्कूटरों पर यात्रा कर रहे थे, तो पुलिस की वर्दी में पुरुषों ने उन पर मशाल की रोशनी चलाई। नतीजतन, मृतक का स्कूटर फिसल गया। इसके बाद, जब गोलियां चलाई गईं तो वे भाग गए और गाँव आ गए। सूचना पर गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। महत्वपूर्ण बात

यह है कि न तो पीडब्लू3 और न ही पीडब्लू6 तीनों अभियुक्तों में से किसी की पहचान कर सके। उन्होंने यह बयान नहीं दिया कि अपराध में शामिल तीन पुलिसकर्मी वे थे जो मुकदमे का सामना कर रहे थे। इस प्रकार, निचली विचारण न्यायालय के विचार में कोई दुर्बलता, बहुत कम विकृति नहीं है कि पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 की गवाही मुकदमे का सामना कर रहे तीन अभियुक्तों के लिए अभियोजन पक्ष के लिए बहुत मददगार नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

29. पीडब्लू-15 की गवाही के संबंध में, निचली विचारण न्यायालय द्वारा उसे अविश्वसनीय और श्रेय के अयोग्य ठहराने के लिए विस्तृत कारण दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा, पीडब्लू15 की उपस्थिति की पुष्टि पीडब्लू3 और पीडब्लू6 द्वारा नहीं की गई है। अन्यथा भी, पीडब्लू15 का एक सप्ताह से अधिक समय तक चुप रहने का आचरण

एच.

476

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

हमारे मन में एक संदेह पैदा होता है कि क्या वह सलाह पर स्थापित एक गवाह है, विशेष रूप से जब हम देखते हैं कि उसका पहला बयान जांच एजेंसी को नहीं था, बल्कि एक वकील द्वारा तैयार किए गए एक हलफनामे पर दिया गया था, जिसने एक साथ तीन हलफनामे तैयार किए थे। निचली विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया और यह भी कि पीडब्लू-15 झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वह हलफनामा तैयार करने के लिए अकेले गया था। निचली विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि तीनों हलफनामे स्टाम्प पेपरों पर तैयार किए गए थे, लगातार क्रमांकित, एक ही विक्रेता से खरीदे गए थे और हलफनामों को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचाते हुए त्वरित उत्तराधिकार में शपथ ली गई थी कि वे एक वकील द्वारा तैयार किए गए थे। निचली विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि पीडब्लू-15 का आचरण इस मायने में थोड़ा असामान्य था कि उसने मृतक के पिता सहित किसी को भी कोई खुलासा नहीं किया, वह तुरंत शपथ लेने गया और पुलिस के एक उच्च अधिकारी को डाक द्वारा एक हलफनामा भेजा, भले ही उस समय तक, जांच स्थानीय पुलिस से सीबी-सी. आई. डी. को स्थानांतरित कर दी गई थी और इसलिए, स्थानीय पुलिस से कोई खतरा नहीं था। इन परिस्थितियों में, यदि निचली विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-15 की गवाही को खारिज कर दिया, तो हमारे विचार में, यह उचित था।

बी.

सी.

डी.

30. सिद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो बात सामने आती है वह यह है कि गवाहों का कहना है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को पुलिस कार्रवाई हुई थी। यह मानते हुए कि यह सच है कि रात में वर्दी में पुरुषों और जनता के सदस्यों के बीच गोलीबारी हुई थी, लेकिन इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि गोलीबारी हत्या के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा, मृतक की मौत राइफल की गोली से नहीं हुई थी। बल्कि, वह ए से मर गया। 12 धारदार बंदूक-गोली जिसका आरोप अभियुक्त व्यक्तियों को जारी की गई राइफलों से नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए, भले ही आरोपी को जारी की गई सर्विस राइफलों से संबंधित राइफल के कारतुसों के खाली हिस्से मौके पर पाए गए हों, लेकिन मृतक की मौत के लिए आरोपी व्यक्तियों का दोष अनुमानित नहीं है। इसके अलावा, ए की कोई वसूली नहीं है। 12 मुकदमे का सामना कर रहे किसी भी आरोपी व्यक्ति से बंदूक ले। विशेष रूप से, घटना के बाद, ग्रामीण अपराध स्थल पर जमा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार, इस अवधि के दौरान आरोपी व्यक्ति मौके पर मौजूद थे। इसलिए, अगर वे वास्तव में शामिल थे तो उन्हें पी. डब्ल्यू. 3 या पी. डब्ल्यू. 6 द्वारा पहचाना जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं थी। इसके अलावा, घटनास्थल पर अभियुक्त की निरंतर उपस्थिति एक ऐसी परिस्थिति है जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है, एक ऐसा आचरण जो एक दोषी दिमाग को नकारता है।

ई.

एफ.

जी.

31. एक अन्य परिस्थिति जो अभियुक्त के पक्ष में जाती है वह है ए

एच.

477

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम श्याम बिहारी और अन्य [मनोज मिश्रा, जे.]

कि अभियोजन पक्ष के अपने मामले के अनुसार, तीन अभियुक्त व्यक्तियों के पास 50 राउंड वाली एक-एक राइफल थी। माना जा सकता है कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर पाए गए कुछ खाली गोलियों को आरोपी को जारी की गई राइफल से नहीं दागा गया था। यह किसी अन्य राइफल की उपस्थिति का भी संकेत है। यह किसकी राइफल थी,

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य मौन हैं। इसके अलावा, अगर आरोपी गोली चलाने के लिए अपनी राइफल का उपयोग करते तो वे मृतक को चोट पहुँचाने के लिए देसी पिस्तौल का उपयोग क्यों करते।

बी.

32. यह परिस्थिति कि अभियुक्त व्यक्तियों को उस क्षेत्र में गश्त करने की आवश्यकता थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उस उद्देश्य के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था, एक ऐसी परिस्थिति है जो निर्णायक नहीं है कि अभियुक्तों पर आरोप लगाया जाए, क्योंकि गश्त क्षेत्र दो गाँवों में फैला हुआ था। यह संभव है कि आरोपी देर से मौके पर पहुँचे, जब घटना पहले ही हो चुकी थी, और उपद्रवियों को भगाने के लिए, उनकी सर्विस राइफलों से गोलियाँ चलाईं। जो भी हो, एक बार जब परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए पीडब्लू-15 के ऑक्युलर खाते को खारिज कर दिया गया था, तो परिस्थितियों को अब तक एक पूरी श्रृंखला बनानी चाहिए थी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं में मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति थे और किसी और ने अपराध नहीं किया था। यहां जो परिस्थितियाँ साबित हुई हैं, वे अब तक एक पूरी श्रृंखला का गठन नहीं करती हैं जो यह इंगित करती हैं कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह आरोपी व्यक्ति थे और कोई और नहीं जिसने अपराध किया था। ऐसी स्थिति में निचली विचारण न्यायालय के पास आरोपी को संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 33. इस स्तर पर, हम रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि विद्वान ए. एस. जी. यह इंगित नहीं कर सके कि विचारण न्यायालय ने किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य को नजरअंदाज विद्वान या गलत पढ़ा।

सी.

डी.

ई.

34. ऊपर बताए गए सभी कारणों से, हम इसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने और मामले को केवल उच्च न्यायालय को निर्णय को फिर से लिखने के लिए भेजने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे विचार में, यह व्यर्थ में एक अभ्यास होगा। याचिका खारिज की जाती है।

एफ.

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

जी.

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

एच.

